भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

16-31 अक्टूबर, 2020

मोदी सरकार मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध

- दिल्ली में कर्बला विश्वविद्यालय की घोषणा
- अफगानिस्तान में तालिबान के साथ समझौते का प्रयास
- इजरायल का अरब जगत में बढ़ता प्रभाव
- ईरान और इराक की सीमा बंद

अनुक्रमणिका

सारांश 02

राष्ट्रीय

मोदी सरकार मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध 03
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी की संभावना 05
दिल्ली में कर्बला विश्वविद्यालय की घोषणा 07
हरियाणा उर्दू अकादमी में लाखों का घोटाला 08
उत्तर प्रदेश में तीन तलाक पीड़ितों को वक्फ फंड से भत्ता 08
30 वर्ष बाद भी भारतीय नागरिकता की तलाश 09

विश्व

अफगानिस्तान में तालिबान के साथ समझौते का प्रयास 10
बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों में हिंसा 12
नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा 13
जिहादियों पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने का आरोप 14
दो टापुओं के प्रश्न पर पाकिस्तान और सिंध में टकराव 15
म्यांमार और चीन की बढ़ती दोस्ती 16

पश्चिम एशिया

इजरायल का अरब जगत में बढ़ता प्रभाव 17
लीबिया में गृह युद्ध की संभावना 18
भारतीयों को उमरा का वीजा जारी करने से इनकार 18
अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान ईरान चीन की शरण में 19
इथोपिया के यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की घोषणा 20

अन्य

ईरान और इराक की सीमा बंद 21
सर सैयद के लेखों का प्रकाशन 21
सब्जियों के मूल्य में भारी वृद्धि 22
किफायती शादी करने का अभियान 22
हैदराबाद नगर की स्थापना का जश्न 23
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग 23

सारांश

विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और अल्पसंख्यकों के बीच खाई पैदा करने का जो प्रयास किया था वह अब विफल हो रहा है। नागरिकता कानून और धारा 370 की आड़ में मोदी सरकार के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था अब कुछ जागरूक मुस्लिम नेताओं ने उसका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से इस सिलसिले में पहल की गई है। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्य सभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम ने एक स्वागत समारोह में भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों मुसलमानों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं और वे उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में मुसलमानों के कल्याण का जितना काम हुआ है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जिलाधिकारी को दिया है। इस संबंध में एक याचिका शौकत भारती द्वारा आयोग में दायर की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 2015 में जब वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश शिया बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने तत्कालीन वक्फ मंत्री मोहम्मद आजम खान के साथ मिलकर प्रयागराज स्थित एक दो सौ वर्ष पुराने इमामबाड़े को गिराकर वहां पर 64 दुकानों के अवैध मार्केट का निर्माण कराया था और इस मामले में करोड़ों का घोटाला हुआ है। वसीम रिजवी प्रारम्भ से ही विवादित व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण की खुलेआम मांग करके मुस्लिम समाज को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया था। इसके कारण उन्हें शिया सम्प्रदाय से भी कुछ व्यक्तियों ने खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार सत्ता में आई तो कई लोगों ने केन्द्रीय वक्फ काउंसिल में ज्ञापन देकर रिजवी पर 70 करोड़ रुपये घोटाले का आरोप लगाया था। इस आरोप की जांच के लिए केन्द्रीय वक्फ काउंसिल ने एक टीम का गठन किया था जिसे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को खंगाल कर अपनी जांच रिपोर्ट वक्फ काउंसिल को सौपने का निर्देश दिया गया था।

अमेरिका अफगानिस्तान के मकड़जाल से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर अमेरिका विश्व के विभिन्न देशों में चल रहे युद्धों में उलझा रहा तो उसकी भारी कीमत राष्ट्रपति के आने वाले चुनाव में उन्हें अदा करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान में सक्रिय जिहादी संगठन अलकायदा से शांति वार्ता पूरी गम्भीरता से शुरू कर दी है। मुख्य वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान से कोई समझौता होता है तो उसका कोई बुरा असर भारत की सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा। यह आश्वासन कितना कारगर होता है अभी इसके बारे में दावा करना कठिन है।

मोदी सरकार मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध

मुसलमानों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो वातावरण बनाया जा रहा था अब वह कमजोर पड़ रहा है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (11 अक्टूबर) के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद जफर इस्लाम को राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के सिलसिले में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने की। इस कार्यक्रम के संयोजक पत्रकार शम्स अल-हिन्दी थे। इस अवसर पर राज्य सभा के नवनिर्वाचित सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आशा से भी अधिक मिल्लत (मुसलमानों) की समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि मुसलमानों को वर्तमान सरकार के बारे में कुछ गलतफहमियां हों मगर हमें अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को नजरअंदाज करके कौम की भलाई के लिए प्रयास करें। सरकार और मुसलमानों के बीच इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए उर्दू प्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने उर्दू पत्रकारों से अनुरोध किया है कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। जफर इस्लाम बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं और उन्होंने अलीगढ़ आदि प्रमुख इस्लामिक संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है। वे राजनीति में इसलिए आए हैं ताकि मुसलमानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकें।

सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि भाजपा के शिखर नेतृत्व में किसी भी सम्प्रदाय के साथ भेदभाव नहीं बरता जाता। उन्होंने कहा कि जब

मुसलमानों की समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अवगत कराया तो उनका रूख आशा से अधिक सकारात्मक था। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि भाजपा में स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोई समस्या हो मगर उसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का रूख हमेशा मुसलमानों के प्रति सहानुभूति का रहा है। यही कारण है कि जब श्रीलंका में ईसाईयों के गिरजाघरों में धमाके हुए तो दिल्ली में सरकार की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया गया था मगर बाद में यह महसूस किया गया कि इससे भारतीय मुसलमानों के खिलाफ गलत संदेश जाएगा तो इस पत्रकार सम्मेलन को अरूण जेटली ने रद्द कर दिया। उन्होनें कहा कि तीन तलाक, धारा 370 या फिर मुसलमानों से संबंधित अन्य शिकायतों को मोदी सरकार ने दूर किया है और इसका कभी राजनीतिक लाभ नहीं उठाया। प्रधानमंत्री मोदी का यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी ऐसे मामले को न उठाया जाए जिससे भारतीय मुसलमानों के खिलाफ वातावरण बने। उन्होंने कहा कि यह प्रचार सरासर गलत है कि भाजपा का रूख मुस्लिम विरोधी है। इस तरह का दुष्प्रचार स्वार्थी तत्वों द्वारा मुसलमानों में भाजपा को बदनाम करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं उर्दू समाचारपत्रों की समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि सरकार उर्दू समाचारपत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुसलमानों में वर्तमान सरकार के खिलाफ भरोसे की कमी है। इसके लिए कुछ तो राजनीतिक दल और कुछ हम स्वयं जिम्मेवार हैं। मेरा यह प्रयास होगा कि सरकार और मुसलमानों के बीच मतभेदों को दूर किया जाए ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मुसलमान अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका कोई केन्द्रीय नेतृत्व नहीं है जिससे सरकार बातचीत कर सके।

इस अवसर पर सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सैयद जफर इस्लाम जैसे जमीनी मुस्लिम नेताओं को प्रोत्साहन देकर यह साफ संकेत दिया है कि वे मुसलमानों का विकास चाहते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना हफीजुर्रहमान की तिलावत-ए-कुरान से हुई। इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व आईआरएस अधिकारी अबरार अहमद, वरिष्ठ पत्रकार सरफराज अहमद आरजू, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप एडिटर इस्माइल जफर खान, कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग आदि ने भी संबोधित किया और यह आशा व्यक्त की कि मोदी सरकार मुसलमानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (13 अक्टूबर) के अनुसार भाजपा मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के नए अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के सम्मान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुसलमानों के उत्थान और कल्याण के लिए जितना काम मोदी के शासनकाल में हुआ है उतना काम देश की आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रयास होना चाहिए कि मुसलमानों और मोदी

सरकार के बीच जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जाए। यह मोदी सरकार के ही प्रयासों का नतीजा है कि हाजियों का कोटा दो लाख तक पहुंच गया है। यह विश्व में सबसे बड़ा कोटा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जैसे यह अहसास हुआ कि आईएएस और आईपीएस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है उन्होंने इसमें वृद्धि करने के लिए ठोस कदम उठाए। सरकारी खर्च पर मुफ्त कोचिंग का प्रबंध किया गया और अखिल भारतीय प्रतियोगी परिक्षाओं में शामिल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों को विशेष छात्रवृत्तियां दी गईं। यही कारण है कि मोदी के शासनकाल में इन अखिल भारतीय सेवाओं में निर्वाचित मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में भारी वृद्धि हुई है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। इस वक्त मुसलमानों की जितनी बड़ी संख्या बीजेपी में है उतनी किसी और पार्टी में नहीं है। मोदी सरकार की जनकल्याण योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान उठा रहे हैं। क्योंकि आज तक उनके साथ किसी भी सरकार ने न्याय नहीं किया था। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वे मुसलमानों की समस्याओं को सरकार से हल करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे और आशा है कि उन्हें इसमें सफलता भी मिलेगी। ■

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी की संभावना

इंकलाब (30 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। प्रयागराज स्थित 200 वर्ष पुराने इमामबाड़े को गिराए जाने के केस में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि 2015 में प्रयागराज स्थित बताशा मंडी के प्राचीन इमामबाड़ा गुलाम हैदर को अवैध रूप से तोड़ दिया गया था और उसकी भूमि पर 64 दुकानों का अवैध निर्माण करा दिया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक याचिकाकर्ता शौकत भारती ने यह आरोप लगाया था कि इस

मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। जब इस इमामबाड़े को गिराकर वहां पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया तो उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार सत्तारूढ़ थी। जबकि मोहम्मद आजम खान वक्फ मंत्री और वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। शौकत भारती ने इस घोटाले के खिलाफ 2016 में जिला प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत की थी मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मंजीत सिंह रॉय ने इंकलाब के प्रतिनिधि को बताया कि पूरे मामले का

अध्ययन करने के बाद आयोग ने जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी वसीम रिजवी और वकार रिजवी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया था मगर वे नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह अपने प्रतिनिधि को भेज दिया था, जिससे आयोग संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे चुकी है तो अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है? शौकत भारती ने दावा किया कि पूर्व वक्फ मंत्री आजम खान के इशारे पर वक्फ में अरबों रुपये का घोटाला हुआ था। केन्द्र सरकार ने धार्मिक स्थान संरक्षण एक्ट 1991 बनाया हुआ है, जिसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इमामबाडे आदि थे उन्हें यथावत रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रयागराज के इमामबाड़े को किस आधार पर गिराया गया? और वहां पर अवैध मार्केट का निर्माण क्यों किया गया? इस बात की जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

इंकलाब (8 अक्टूबर) के अनुसार सेंट्रल वक्फ काउंसिल की एक विशेष टीम ने शिया वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड की बारिकी से जांच की। अब यह जांच कमेटी केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केन्द्रीय जांच टीम के सदस्य हनीफ अली और राहत वसीम खान ने कहा कि इस जांच के दौरान उनके हाथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं मगर उन्होंने इस संबंध में किसी तरह की विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया और कहा कि वे इसका उल्लेख अपनी जांच रिपोर्ट में ही करेंगे। उन्होंने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड में घोटालों के बारे में केन्द्रीय वक्फ काउंसिल के पास कई ज्ञापन प्राप्त हुए थे, जिनके कारण इस जांच टीम का गठन किया गया था। इस टीम में पांच सदस्य शामिल हैं। वसीम राहत खान ने पत्रकारों को बताया कि उनका लक्ष्य वक्फ संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त करवाना और घोटालों की जांच करना है। क्योंकि वक्फ संपत्ति पूरी मिल्लत की है। इसलिए उसमें किसी तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी: वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद विवादों में हैं। गत वर्ष नवम्बर महीने में उन्होंने मांग की थी कि शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। विवादित ढांचे के बदले में अगर मुसलमानों को लखनऊ के हुसैनाबाद में मस्जिद बनाने के लिए एक एकड़ भूमि दे दी जाए तो वे उससे संतुष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से तीन तलाक के मुद्दे पर जब अधिकांश मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे तो रिजवी ने इस कानून का खुलेआम समर्थन किया था और मांग की थी कि तीन तलाक के दोषियों को कम-से-कम दस वर्ष की सजा दी जाए। इससे एक महीने पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना की जाती है तो शिया वक्फ बोर्ड की ओर से वे चांदी का तीर-कमान इस प्रतिमा के लिए भेंट करेंगे। उनके इस रूख को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अन्य सभी मुस्लिम नेता उनके खिलाफ संगठित हो गए थे। विख्यात शिया नेता मौलाना कल्बे जवाद ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमें उन पर आरोप लगाया था कि वे समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत पैदा कर रहे हैं। इमाम फाउंडेशन के आरिफ कासमी ने भी एक पत्रकार सम्मेलन में यह आरोप लगाया था कि आजम खान के साथ मिलकर वसीम रिजवी ने वक्फ संपत्ति में कम-से-कम 70 करोड़ का घोटाला किया है। इसलिए उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम नेताओं ने वसीम रिजवी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का

भी डटकर विरोध किया था जिसमें रिजवी ने आरोप लगाया था कि इस्लामिक मदरसों में आईएसआईएस के सिद्धांतों की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस्लामी मदरसे खुलेआम आतंकवाद का प्रचार कर रहे हैं। उनके इस आरोप का खंडन करते हुए दिल्ली के पूर्व विधायक हुसैन अहमद का कहना था कि यह आरोप सरासर निराधार है। मदरसों की भूमिका देश के स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक रही है और वसीम रिजवी इस तरह का बेबुनियाद आरोप सत्ता में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए लगा रहे हैं। वसीम रिजवी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो समर्थन किया था उससे विश्व के शियाओं में भारी रोष पैदा हो गया था। इराक के शिया प्रमुख अयातुल्लाह अली अल-सिस्तानी ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें वसीम रिजवी को शिया समुदाय से खारिज कर दिया गया था।

दिल्ली में कर्बला विश्वविद्यालय की घोषणा

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार इमाम हुसैन के चेहल्लुम के अवसर पर दिल्ली की दरगाह शाह मर्दान में एक मजलिस का आयोजन किया गया जिसे मौलाना अजहर हुसैन जैदी, मौलाना हसन कमैली और शिया विद्वान मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने संबोधित किया। इस अवसर पर परम्परा के अनुरूप अंजुमन हैदरी की ओर से अल्म मुबारक और शिबिया ताबूत हजरत इमाम हुसैन निकाला गया और उसे मातमी जुलूस में कर्बला में ले जाकर दफन कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि दिल्ली पुलिस ने हजरत इमाम हुसैन के चेहल्लुम के अवसर पर कोरोना की महामारी को देखते हुए नगर के विभिन्न भागों से शियाओं को ताजिए निकालने की अनुमति नहीं दी थी। मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि दिल्ली के जोरबाग कर्बला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कर्बला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने जो वायदा किया है उसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि कर्बला विश्वविद्यालय को स्थापित करने के प्रश्न पर शिया नेताओं में गम्भीर मतभेद हैं। गत कई दशक से जोरबाग कर्बला की हजारों करोड़ के मूल्य की भूमि विवाद का विषय बनी हुई है। इस समय 70 एकड़ की यह भूमि नई दिल्ली के सबसे महंगे क्षेत्र में स्थित है। इसलिए इस भूमि पर सब की नजर लगी हुई है। इस समय इस कर्बला का प्रबंधन अंजुमन हैदरी के जिम्मे है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार में कहा गया है कि इमाम हुसैन के चेहल्लुम के अवसर पर दिल्ली की दरगाह शाह मर्दान में अंजुमन हैदरी द्वारा आयोजित मजलिसों में जनता की भारी भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे। अंजुमन हैदरी के सचिव सैयद बहादुर अब्बास ने इन पाबंदियों को गैरकानूनी करार दिया था। जब पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले शियाओं को दरगाह में जाने से रोक दिया तो उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए बेरिकेडों के सामने ही मातम शुरू कर दिया। इस पर अंजुमन हैदरी के पदाधिकारियों और पुलिस में काफी नोकझोंक हुई। बहादुर अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार लॉकडाउन खोल चुकी है इसलिए इस दौरान मातम करने वालों को दरगाह तक जाने से रोकना सरासर गैरकानूनी है।

हरियाणा उर्दू अकादमी में लाखों का घोटाला

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार हरियाणा उर्दू अकादमी में 15 लाख रुपये के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस संदर्भ में अकादमी के पूर्व निदेशक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि यह घोटाला लेखकों के आतिथ्य और कर्मचारियों के टीए-डीए के खर्च में हुआ है। जो फर्जी बिल पास किए गए थे उनके चेक नौकरों और ड्राइवरों के नाम जारी किए गए थे और यह धनराशि तत्कालीन निदेशक ने हड़प ली थी। हाल ही में हरियाणा के सूचना निदेशालय के अकाउंट ऑफिसर द्वारा की गई जांच के अनुसार 2018 में अकादमी में 15 करोड़ का घोटाला हुआ। जांच में यह पाया गया है कि विभिन्न लेखकों के नाम पर एक-एक दिन में तीन-तीन फर्जी बिल बनाए गए और दो बार सरकारी कार की बीमा के नाम पर धनराशि बटोरी गई। यात्रा भत्ते के फर्जी बिल भी बनाए गए। विजिलेंस विभाग ने तत्कालीन निदेशक डॉ. नरेन्द्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले की जांच का काम डीएसपी शरीफ सिंह को सौंपा गया है। जांच अधिकारी के अनुसार 2 फरवरी, 2018 को लेखकों के भोजन पर 25 हजार रुपये का खर्च दिखाया गया और इसी तरह से 16 जुलाई को 14000 रुपये का खर्च दिखाया गया। इसके तीन दिन बाद फिर खाने का खर्च 8900 बताया गया। ये सभी रकम कार चालक प्रमोद कुमार के नाम जारी चेकों से वसूली गई। जांच अधिकारी को चालक ने बताया कि उसे तत्कालीन निदेशक ने जैसा निर्देश दिया था वैसा ही उसने किया है। हमसे कई बिलों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1 लाख 26 हजार रुपये का एक अन्य चेक चपरासी कपूर चंद के नाम पर जारी हुआ। यह रकम भी निदेशक ने स्वयं ही ले ली। यात्रा भत्ते के फर्जी बिल बनाकर एक लाख रुपये वसूल किए गए जबकि 18 अक्टूबर, 2018 को सरकारी खाते से चार लाख 92 हजार रुपये की धनराशि एक निजी खाते में ट्रांसफर की गई, जिसके लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। यह खाता निदेशक के एक रिश्तेदार का था। दिल्ली की एक दुकान से 96 हजार रुपये का सामान खरीदने का दावा किया गया था और इस संबंध में बिल भी पेश किए गए थे जो जांच किए जाने पर फर्जी पाए गए। दिल्ली की जिस दुकान से यह समान खरीदने का दावा किया गया था उसके दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान से कोई माल नहीं खरीदा गया है।

उत्तर प्रदेश में तीन तलाक पीड़ितों को वक्फ फंड से भत्ता

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को वक्फ बोर्ड की ओर से मासिक भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जो महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ केस दायर करेंगी उन्हें सरकार की ओर से केस का निपटारा होने तक हर महीने पांच-पांच सौ रुपये भत्ता दिया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग के सचिव बी.एल. मीणा ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को यह निर्देश दिया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक राज्यव्यापी कार्यक्रम तैयार किया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को यह निर्देश

दिया गया है कि वह इस बात की जांच करे कि राज्य के प्रत्येक जिले में तीन तलाक से प्रभावित कितनी महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त वक्फ विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि वह तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास और उनके स्थाई गुजारा भत्ते की व्यवस्था करने के लिए तुरंत योजना बनाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कार्यकारी प्रमुख एस.एम. शोएब ने कहा है कि जो महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ केस दायर करती हैं उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके गुजारे की कोई व्यवस्था नहीं होती। जब तक न्यायालय इस संबंध में उनके लिए भत्ते की व्यवस्था नहीं करती तब तक राज्य सरकार उनके गुजारे के लिए भत्ता देती रहेगी। इसके बाद ही राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि उन्हें वक्फ की आय से हर महीने नियमित रूप से गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था की जाए।

30 वर्ष बाद भी भारतीय नागरिकता की तलाश

इंकलाब (12 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के शहर लाहौर की रहने वाली सबा फरहत की शादी 30 वर्ष पूर्व मेरठ निवासी फरहत मसूद से हुई थी। निकाह के बाद सबा पाकिस्तान छोड़कर भारत में तो बस गई मगर लाख प्रयास करने के बावजूद वह अभी तक भारतीय नागरिक नहीं बन पाई। सबा ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 29 वर्षों से वह सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर चुकी है। मगर उसकी फाइल जिला प्रशासन के कार्यालयों में उलझकर रह गई है। गत 29 वर्षों से वह विजिटर वीजा पर भारत में रह रही है और उसे कई बार नजरबंद भी किया गया है। यहां तक कि उसे पाकिस्तान वाले भी वीजा नहीं देते। सबा ने कहा कि परम्परा के अनुसार उसकी शादी उसके परिवारजनों के सहयोग से हुई थी और वह 30 वर्षों से अपने बच्चों और पति के साथ मेरठ में रह रही है। वह भारत की बहु तो बन गई मगर भारतीय नागरिक नहीं बन सकी। उसने कहा कि वह ताजमहल को देखना चाहती थी मगर अभी तक वह ताजमहल को नहीं देख सकी क्योंकि विजिटर वीजा के अनुसार उसे मेरठ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसी तरह से जब उसने अपनी पुत्री को नोएडा के एक शिक्षा संस्थान में दाखिल करवाया था तो वह उसके साथ वहां रहना चाहती थी मगर सरकार ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी। न ही उसे अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए मेरठ से बाहर जाने की ही अनुमति प्राप्त है। उसे आशा है कि समाचारपत्रों में उसकी व्यथा प्रकाशित हो जाने के बाद उसे सरकार से न्याय मिलेगा और उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी।

ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व बुलंदशहर की रहनेवाली एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक फाखरा नौरीन को 30 वर्ष के प्रयास के बाद भारतीय नागरिकता मिली है। मेरठ की नादिर अली बिल्डिंग में रहने वाली सबा फरहत की बेटी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील है और उसका नाम ऐमन फरहत है। उसने कहा कि हम अपनी नागरिकता के लिए सभी जरूरी दस्तावेज मेरठ के कार्यालय में जमा करवा चुके हैं। मगर न जाने क्यों कई दशकों से मेरी मां की फाइल कार्यालयों में लटकी हुई है।

अफगानिस्तान में तालिबान के साथ समझौते का प्रयास

इत्तेमाद (10 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इस वर्ष क्रिसमस तक अमेरिका की सारी फौज वापस अपने देश आ जानी चाहिए। ज्ञातव्य है कि इसी साल फरवरी महीने में अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि तालिबान अफगानिस्तान में अपनी हिंसक गतिविधियां बंद कर देंगे और अमेरिका अफगानिस्तान से मई 2021 तक अपनी सेना वापस बुला लेगा। इसके बदले में तालिबान ने स्थाई युद्ध बंदी और अफगानिस्तान के साथ सत्ता में भागीदारी का भी आश्वासन दिया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि इस वर्ष के अंत तक अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी फौजियों की संख्या ढ़ाई हजार तक घटा देगा। मगर अब ट्रम्प इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। हालांकि अभी तक इराक और सीरिया में भारी संख्या में अमेरिकी फौजी मौजूद हैं।

इत्तेमाद (11 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान में शांति वार्ता के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने हाल ही में भारत की यात्रा की है और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान से होने वाला समझौता भारत के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भारत पर निर्भर है कि वह अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान से किसी तरह की वार्ता करना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि यह आशंकाएं निराधार हैं कि अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान अपना अगला निशाना भारत को बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता की हमारी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अगर तालिबान के साथ शांति समझौता होता है तो वह अफगानिस्तान के पहाड़ी

और अन्य क्षेत्रों में सभी सैनिक गतिविधियां बंद कर देंगे। भारत हमारा दोस्त है। इसलिए हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे भारत को परेशानी हो। अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि इस समझौते से भारत को कोई परेशानी न हो।

दैनिक सियासत (12 अक्टूबर) के अनुसार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि वे तालिबान से यह आश्वासन लेंगे कि वे भारत में किसी भी तरह की गतिविधियों में भाग न लें। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के नवनिर्माण में अपना शानदार सहयोग दिया है और अब तक वह तीस लाख डॉलर अफगानिस्तान को सहायता दे चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में होने वाले शांति समझौते का समर्थन किया है क्योंकि अफगानिस्तान में शांति स्थापना भारत के भी हित में होगी। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भारत आने से पूर्व पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से भी तालिबान के साथ होने वाले समझौते के बारे में बातचीत की थी।

इत्तेमाद (10 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद मासूम स्तानेकजई ने कहा है कि कतर की राजधानी दोहा में तालिबान इस्लामिक मुवमेंट के साथ जो शांति वार्ता चल रही थी उसका आधार कुरान और सुन्नत थी। इसलिए उन्हें इस बात का विश्वास है कि तालिबान कुरान का पालन करेंगे। हम यह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति हो और खून खराबे से हमें मुक्ति मिले। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हालांकि दोहा में शांति समझौता हो चुका है मगर इसके बावजूद अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में जंग जारी है। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने एक पुलिस केन्द्र पर हमला किया था, जिसमें सात पुलिस वाले मारे गए थे और चार लापता हो गए थे। इसी तरह से अफगानिस्तान के हेरात सूबे में एक बस में हुए बम धमाके में कई लोग मारे गए। यह बस हेरात से काबुल जा रही थी। कांधार के समीप एक बारूदी सुरंग के फटने से यह धमाका हुआ। पुलिस ने इस धमाके के लिए तालिबान को दोषी ठहराया है। तालिबान ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दोहा में हुए शांति समझौते की सफलता पर संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह वार्ता गतिरोध का शिकार हो गई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि तालिबान को इस्लाम के हितों के खातिर युद्धविराम स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 20 वर्ष से जो युद्ध चल रहा है उसे 20 दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी कई जटिल मुद्दे बाकी हैं। उदाहरण के तौर पर अभी अफगानिस्तान में भविष्य में कैसा शासनतंत्र होगा इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तालिबान अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर का कहना है कि अभी समझौते के रास्ते में कई बाधाएं हैं। कई विवादित मुद्दों का हल नहीं निकल सका है। इसलिए इस समझौते से बहुत लम्बी चौड़ी आशा करना गलत होगा।

हमारा समाज (10 अक्टूबर) के अनुसार अफगान तालिबान ने हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका क्रिसमस तक सभी अमेरिकी फौजियों को वापस बुला लेगा। मगर विश्लेषकों का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो इससे वर्तमान

अफगान सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और सारी सत्ता तालिबान के हाथ में चली जाएगी। अफगानिस्तान की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। किंतु अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि गत छह महीनों से अफगानिस्तान में जो सैनिक अभियान तालिबान के खिलाफ हो रहा है वह अफगान सेना कर रही है और इसमें अमेरिकी सैनिकों का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान के विश्लेषक जाहिद हुसैन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के हटने के बाद गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जिससे इस सारे क्षेत्र का अमन व शांति खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अफगानिस्तान से ज्यादा अपने देशवासियों की चिंता है जो निरंतर उन पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला ले। क्योंकि अमेरिकी अफगानिस्तान में लम्बी जंग से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से अफगानिस्तान युद्ध की विभिषिका को झेल रहा है। जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया तो इसके बाद वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया और अमेरिका ने तालिबान की आड़ में वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तालिबान को अमेरिका ने ही पैदा किया था। यह अलग बात है कि अब तालिबान अमेरिका के नियंत्रण में नहीं रहे हैं। जाहिद हुसैन का कहना है कि अमेरिका को युद्ध की विभिषिका से निकालने का वायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के भावी चुनावी अभियान का हिस्सा है।

बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों में हिंसा

सियासत (11 अक्टूबर) के अनुसार दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों पर सशस्त्र बांग्लादेशियों ने हमला कर दिया जिसके कारण कम-से-कम आठ लोग मारे गए और इन शिविरों से हजारों लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। प्रशासन ने गोलाबारी और अपहरण के अनेक केस दर्ज किए हैं और इस संबंध में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकारी सूत्रों के अनुसार छह से सात लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के दो दर्जन से अधिक शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। स्थानीय निवासी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशियों में निरंतर सशस्त्र झड़प होती रहती है। सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर कॉक्स बाजार में हैं जिसमें एक लाख शरणार्थी रह रहे हैं। पुलिस कप्तान रफीक उल इस्लाम के अनुसार गत एक सप्ताह से इस क्षेत्र में सशस्त्र झड़पें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन झड़पों के पीछे मादक पदार्थों के तस्करों का हाथ है जो म्यांमार से तस्करी करना चाहते हैं। इन तस्करों के कई गिरोह हैं जो एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शिविर म्यांमार सीमा के समीप स्थित है। और कॉक्स बाजार नगर से चालीस किलोमीटर दूर है। यह शिविर छह हजार एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना काफी कठिन है।

नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा

हमारा समाज (12 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर के साथ-साथ 40 अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। लाहौर पुलिस ने इस मुकदमें को दर्ज किए जाने के बाद एक विशेष जांच टीम गठित की है। यह मुकदमा नवाज शरीफ की पुत्री मरयम नवाज, पूर्व मंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और तीन पूर्व सैनिक जनरलों के खिलाफ दर्ज किया गया है। फारूक हैदर ने कहा कि उन्होंने कश्मीर के मामले पर हमेशा भारत का डटकर विरोध किया है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के कारण सबसे ज्यादा खुशी भारत के प्रधाानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ही होगी। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की कि इमरान खान की सरकार की नजर में सभी विपक्षी पार्टियों के नेता भारत के एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा? यह केस पीटीआई के बदर रशीद की याचिका पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग के नेता मुल्क के गद्दार हैं। वे विदेशों में बैठे हुए पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री फारूक हैदर उस वक्त लंदन में मौजूद थे जब नवाज शरीफ के भाषण को सीधा लंदन से पाकिस्तान में प्रसारित किया गया था। इसलिए वर्तमान सरकार को अस्थिर करने में उनका भी बराबर का हिस्सा है। लाहौर क्षेत्र के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ईनाम गनी ने कहा कि चार सदस्यीय जांच टीम का नेतृत्व पुलिस कप्तान आसिम इफ्तेखार करेंगे और उनके अतिरिक्त इस टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद ग्यास, इंस्पेक्टर तारिक, इंस्पेक्टर इल्यिास कियानी और सब इंस्पेक्टर शब्बीर अगवान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जांच टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस मुकदमें में जो अन्य महत्वपूर्ण नेता आरोपी हैं उनमें राजा जफरूल्लाह, हसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ आदि शामिल हैं। एक अन्य मुकदमें में उच्च न्यायालय को इस बात की सूचना दी गई है कि नवाज शरीफ के बेटे ने लंदन में समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं।

जिहादियों पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने का आरोप

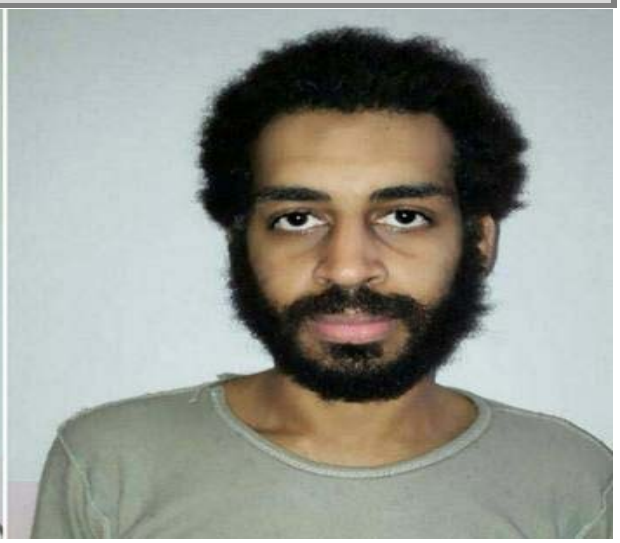

हमारा समाज (9 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका की एक न्यायालय ने ब्रिटेन निवासी आईएसआईएस के दो आतंकवादियों को दो अमेरिकी नागरिकों की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है। इन दोनों अपराधियों को ब्रिटेन ने अगस्त महीने में अमेरिका के हवाले किया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन ने इन जिहादियों को इस शर्त पर अमेरिका के हवाले किया था कि अगर उनके खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। ब्रिटिश न्यायालय ने इन दोनों को अमेरिका के हवाले करने से पूर्व उनके विषय में अमेरिकी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर विचार करने के बाद इन दोनों को अमेरिका के हवाले किया गया था। जबकि ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी संगठन से संबंधित होने के कारण उनकी ब्रिटिश नागरिकता रद्द कर दी थी। पुलिस के अनुसार ब्रिटिश मूल के 36 वर्षीय अलेक्जेंडा कोटे और 32 वर्षीय अल-सफी अल-शेख आईएसआईएस के एक सेल का हिस्सा थे। ये लोग विदेशी नागरिकों का अपहरण करके उनके सिर काटने का वीडियो भी जारी करते थे। इस गिरोह के चार सदस्यों में से एक 2015 में मारा गया था जबकि दूसरा गिरफ्तार हो गया था। बाकी दो व्यक्तियों को 2018 में अमेरिकी सेना ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वे सीरिया से तुर्की फरार होने का प्रयास कर रहे थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र का कहना है कि हम अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले इन आतंकवादियों को निश्चित रूप से सजा देंगे। इन आतंकवादियों के हाथों जो अमेरिकी मारे गए हैं उन्हें हम वापस नहीं ला सकते। फिर भी उनके परिवारजनों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। इस ग्रुप के हाथों मारे जाने वालों में अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोली और स्टीवेन सोटलोफ शामिल हैं। बताया जाता है कि आईएसआईएस के इस सेल ने दहशत पैदा करने के लिए अमेरिकियों के अतिरिक्त ब्रिटिश और जापानी नागरिकों की भी सार्वजनिक रूप से तलवार से गर्दन उड़ाकर हत्या की थी। इनके खिलाफ सीरिया में दो दर्जन से अधिक लोगों का अपहरण करने का आरोप है।

दो टापुओं के प्रश्न पर पाकिस्तान और सिंध में टकराव

हमारा समाज (12 अक्टूबर) के अनुसार कराची के समीप समुद्र में स्थित दो टापुओं की मिल्कियत के सवाल पर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार और सिंध सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया है। सिंध सरकार का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने दो टापुओं बुंडल और बुड्डो के बारे में जो अध्यादेश जारी किया है वह गैरकानूनी है। सिंध सरकार ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय असेम्बली में विरोध प्रकट किया है। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने सिंध सरकार पर राजनीति खेलने का आरोप लगाया है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का कब्जा है तो सिंध पर भुट्टो की पीपुल्स पार्टी की सरकार है। इसके अतिरिक्त सिंध सरकार ने सिंध उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है जिसमें इन द्वीपों का नियंत्रण इमरान सरकार को सौपने का विरोध किया गया है। न्यायालय ने इस संदर्भ में पाकिस्तान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ज्ञातव्य है कि गत महीने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इन दोनों टापुओं पर इमरान सरकार का नियंत्रण होगा और उनका प्रबंधन पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। इस अथॉरिटी का मुख्यालय कराची में होगा और अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय होंगे। इस अथॉरिटी के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यह अथॉरिटी सभी सम्पत्ति की मालिक होगी और वह विभिन्न कर, शुल्क और ट्रांसफर चार्जेज लगा सकेगी। इस अथॉरिटी का प्रमुख आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल दर्जे का अधिकारी होगा, जिसकी कार्यावधि चार वर्ष की होगी। इसमें यदि सरकार चाहे तो विस्तार भी कर सकती है। समुद्री मामलों से संबंधित मंत्रालय के मंत्री अली जैदी ने यह दावा किया है कि सिंध सरकार ने संघीय सरकार को यह आश्वासन दिया था कि वह इन दोनो टापुओं को इमरान सरकार के हवाले कर देगी इसलिए हमने अध्यादेश जारी करके कोई गैरकानूनी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीपुल्स पार्टी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। हालांकि इससे पूर्व राज्य सरकार ने बुंडल द्वीप के बारे में एक पत्र इमरान सरकार को लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि संघीय सरकार के अनुरोध पर स्थानीय जनता और मछुआरों के हितों के संरक्षण के लिए यह द्वीप संघीय सरकार के हवाले किया जा रहा है। सिंध के सूचना मंत्री नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इमरान सरकार देश की जनता को मूर्ख बना रही है। यदि ये दोनों द्वीप उसके थे तो उसने राज्य सरकार से एनओसी क्यों मांगी थी? उन्होंने कहा कि सिंध सरकार ने यह कहां लिखा है कि यह भूमि आपकी है? हमने तो सिर्फ स्थानीय लोगों के हितों के लिए वहां पर संघीय सरकार को निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। सिंध सरकार ने बाद में इस पत्र को वापस ले लिया था। राज्य सरकार का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस पत्र को जारी करने का विरोध किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड के अनुसार ये दोनों टापू राज्य सरकार की मिल्कियत हैं। सिंध सरकार के प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया है कि इमरान सरकार ने यह अध्यादेश जारी करके सिंध और बलूचिस्तान जैसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर छापा मारा है।

म्यांमार और चीन की बढ़ती दोस्ती

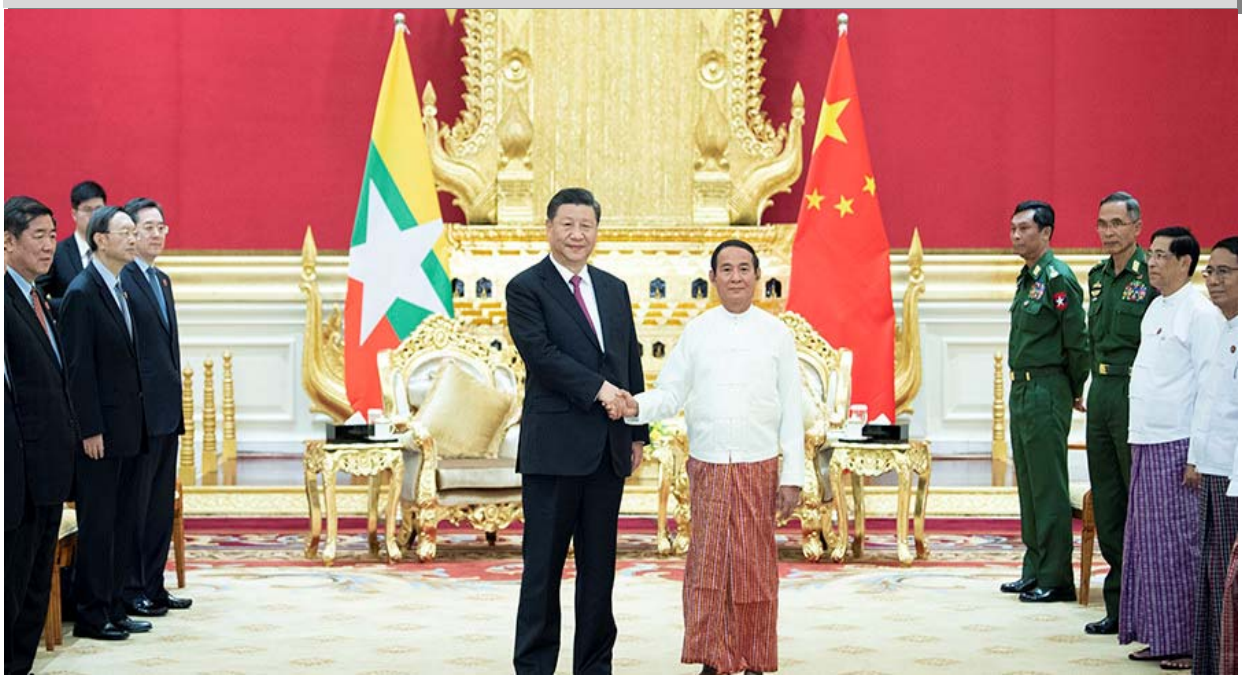

हमारा समाज (12 अक्टूबर) के अनुसार म्यांमार के साथ चीन की बढ़ती हुई मित्रता पर भारत सरकार के राजनयिकों ने चिंता प्रकट की है। म्यांमार में पूर्व भारतीय राजदूत राजीव भाटिया ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हाल ही में भारत के विदेश सचिव व सेना प्रमुख म्यांमार के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त म्यांमार में सत्ता के दो केन्द्र उभर रहे हैं। सेना और सरकार के बीच टकराव की सम्भावना पैदा हो गई है। सेना के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान सूकी दो समानांतर केन्द्रों के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती है। विदेश मंत्रालय यह महसूस करता है कि म्यांमार भारत की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है और अगर इस क्षेत्र पर चीन का प्रभाव बढ़ता है तो इसके कारण भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि चीन ने हाल ही में म्यांमार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 1700 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण किया है जो चीन और पाकिस्तान को म्यांमार से जोड़ती है। यह पाकिस्तान और चीन के आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि चीन अब आसानी के साथ बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। इस सड़क का निर्माण चीन ने एक विशेष लक्ष्य से किया है जिसे भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश हो सकती है। इस सड़क का निर्माण चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके किया है। चीन इसे बांग्लादेश के साथ भारत से जोड़ना चाहता था और उसने यह दावा किया था कि इससे भारत के साथ चीन और बांग्लादेश के व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। मगर भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्योंकि भारत का दृष्टिकोण यह है कि इससे भविष्य में भारत के लिए खतरा हो सकता है। चीन धीरे-धीरे मोतियों की माला के नीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है।

इजरायल का अरब जगत में बढ़ता प्रभाव

हमारा समाज (10 अक्टूबर) के अनुसार मुस्लिम देश सूडान में दिन-प्रतिदिन संकट बढ़ता जा रहा है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और खाद्यान न मिलने के कारण अकाल का खतरा देश पर मंडरा रहा है। जनविरोध के कारण सूडान में डेढ़ वर्ष तक सत्तारूढ़ रहने के बाद राष्ट्रपति उमर अल-बशीर की सरकार को जनाक्रोश के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। इस स्थिति का लाभ उठाकर इजरायल सूडान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। सूडान अगर इजरायल को मान्यता दे देता है तो अमेरिका उसे आतंकवादी जिहादियों का समर्थक होने की सूची से निकाल देगा। इससे सूडान को संकट से मुक्ति मिल सकती है। इजरायल सूडान में अपना पैर इसलिए जमाना चाहता है क्योंकि आतंकवादी संगठन अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठन सूडान की भूमि से मिस्र, अरब, यूथोपिया, यूगांडा और कीनिया में अमेरिकी और उनके समर्थकों को अपना निशाना बना रहे हैं। 1993 में न्यूयॉक के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने सूडान को आतंकवादियों का समर्थक करार दिया था और उसपर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने सूडान को मजबूर किया था कि वह अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन और अन्य जिहादियों को अपने देश से निष्कासित कर दे। इसके बाद अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए ने सूडान में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया था। मगर अमेरिका की योजना विफल रही और उमर अल-बशीर की इस्लामिक सरकार ने ईरान के आतंकवादी संगठनों और हमास से अपने तार जोड़ लिए। कम-से-कम दो अवसरों पर इजरायल के जंगी विमानों ने सूडान के वाहनों के दो काफिलों पर हमला

किया जो कि इस्लामिक जिहादी संगठन हमास के लिए अस्त्र-शस्त्र ले जा रहे थे। क्योंकि अमेरिका ने सूडान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं इसलिए विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सूडान को किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार सूडान के 96 लाख लोग भूखमरी के शिकार हैं।

सियासत (11 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब का इजरायल की ओर झुकाव बढ़ रहा है। हाल ही में इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इससे पूर्व सिर्फ दो अरब देशों के साथ इजरायल के राजनीतिक संबंध थे। इनमें मिस्र और जॉर्डन शामिल हैं। अरब जगत के विश्लेषकों का मत है कि अमेरिका तुर्की की स्थिति को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे इजरायल और अरब देशों के संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका एक कारण यह है कि तुर्की के साथ रूस के संबंधों में दिन-प्रतिदिन मजबूती आ रही है। हाल ही में तुर्की को भारी मात्रा में रूसी अस्त्र-शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। फिलिस्तीनी नेताओं का आरोप है कि अमेरिका ने इजरायल की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम देशों को दो गुटों में विभाजित कर दिया है। एक गुट का नेता तुर्की है जबकि दूसरे का सऊदी अरब है।

लीबिया में गृह युद्ध की सम्भावना

इत्तेमाद (10 अक्टूबर) के अनुसार लीबिया की सरकार ने अपनी सेनाओं को सतर्क कर दिया है क्योंकि लीबिया में गृह युद्ध तेज होने की संभावना है। खलीफा हफ्तर के नेतृत्व में लीबिया के विद्रोही पश्चिम में स्थित अनेक नगरों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लीबिया सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी बहादुर और दिलेर फौजों ने रक्षा मंत्री की हिदायत पर मोर्चे सम्भाल लिए हैं ताकि किसी भी हमले का मुकाबला किया जा सके। लीबिया के रक्षा मंत्री हाल ही में तुर्की का दौरा करके वापस लौटे हैं। बताया जाता है कि तुर्की के गुप्तचर सूत्रों ने उन्हें इस बात की चेतावनी दी है कि विद्रोही लीबिया के कुछ नगरों पर हमला कर सकते हैं। विद्रोहियों की सेना भारी संख्या में इस क्षेत्र में एकत्र हो चुकी है। लीबिया में गत कई महीनों से गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की द्वारा संघीय सरकार को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई किए जाने के कारण इस युद्ध में और भी तेजी आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास कर रहा है कि लीबिया में गृह युद्ध को रोका जाए। इस संबंध में संघीय सरकार और लीबिया की संसद से बातचीत का सिलसिला जारी है मगर अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है।

भारतीयों को उमरा का वीजा जारी करने से इनकार

सियासत (8 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी सरकार द्वारा उमरा के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी किए जाने की फिलहाल कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि सऊदी अरब ने यह स्पष्ट किया है कि जिन देशों में कोरोना की महामारी फैली हुई है वहां के नागरिकों को वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सऊदी सरकार ने विश्व भर के वृद्धों को भी उमरा का वीजा जारी करने से इनकार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि कोरोना महामारी से पूर्व 40 लाख लोग उमरा के लिए सऊदी अरब की यात्रा करते थे। कोरोना के कारण सऊदी सरकार ने अपनी सीमाएं विदेशों के लिए बंद कर दी थीं और मक्का मदीना को भी इस्लाम के इतिहास में पहली बार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। हाल ही में आंशिक रूप से सऊदी सरकार ने उमरा की अनुमति देने की घोषणा की थी। इसके बाद लाखों भारतीय श्रद्धालुओं को यह आशा बंध गई थी कि वे शीघ्र ही उमरा की यात्रा कर सकेंगे। मगर अब सऊदी सरकार ने कोरोना ग्रस्त भारतीयों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने ट्रेवल एजेंटों को यह भी निर्देश दिया है कि जब तक सऊदी सरकार भारतीयों को वीजा जारी करने की घोषणा नहीं करती तब तक वह किसी तरह की बुकिंग न करें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने मक्का के काबा और मदीना की नबवी मस्जिद में कोरोना नाशक सर्वे के लिए रोबोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। काबा के प्रमुख डॉ. अब्दुल रहमान अल-सीसी ने स्मार्ट रोबोट व्यवस्था का उद्घाटन किया। ये रोबोट बंद स्थानों में कीटनाशक स्प्रे करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रोबोट की आधुनिक व्यवस्था के कारण कोरोना को रोकने में सहायता मिलेगी। इन रोबोट को भारी संख्या

में विदेशों से मंगाया गया है। ये रोबोट बैटरी पर चलते हैं और आठ घंटे तक स्प्रे कर सकते हैं। इनमें 24 लीटर स्प्रे को स्टोर किया जा सकता है। इनकी क्षमता एक घंटे में दो लीटर स्प्रे करने की है। ये बैटरी से चलते हैं और अति आधुनिक यंत्रों से लैश हैं।

सियासत (9 अक्टूबर) के अनुसार उमरा के इतिहास में पहली बार मक्का के होटलों के किराए में भारी कटौती की गई है। कुछ क्षेत्रों में तो होटलों के कमरों का किराया 38 रियाल से भी कम कर दिया गया है। कोरोना की महामारी के कारण सऊदी होटल उद्योग को जो भारी झटका लगा है उससे उबरने का प्रयास हो रहा है। सऊदी अरब के पवित्र नगर मक्का में 1400 से अधिक होटल हैं जो कि देशभर में होटलों का दो तिहाई हिस्सा हैं। आमतौर पर इन होटलों में इन कमरों का किराया 250 से 700 सऊदी रियाल के बीच होता था। मक्का चेंबर्स ऑफ कॉमर्स

एंड इंडस्ट्री में होटल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्लाह फाली ने कहा कि कोरोना की महामारी के कारण होटल उद्योग को भारी झटका लगा है और उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देने और भवनों की देखभाल करने में भी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सऊदी सरकार ने उमरा करने के इच्छुकों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके कारण यात्रियों के कम संख्या में आने की संभावना है। इसलिए फिलहाल सीमित संख्या में होटलों को खोला जा रहा है। ■

अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान ईरान चीन की शरण में

इत्तेमाद (12 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के कारण ईरान ने चीन से संबंधों को सुधारने के ताजा प्रयास शुरू कर दिए हैं। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन का दौरा किया है। जरीफ ने कहा कि ईरान ने चीन के साथ रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने तथा कोरोना के लिए संयुक्त रूप से टीका बनाने आदि मामलों पर सहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु संधि का चीन ने समर्थन करने की घोषणा की है। अमेरिका के साथ ईरान के संबंध दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर यह आरोप लगाया है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है इसलिए अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन देशों पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि वह ईरान को अस्त्र-शस्त्रों की बिक्री फोरन बंद कर दें और इस बात का ठोस प्रयास करें जिससे कि ईरान परमाणु क्षेत्र में यूरेनियम संवर्द्धन के कार्यक्रम से दूर रहे। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर अनेक नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं जिसके तहत अमेरिका में 18 ईरानी बैंकों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जाता है कि यूरोपीय देशों ने अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है क्योंकि इस तरह से ईरान के साथ उनके व्यापारिक हितों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ■

इथोपिया के यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की घोषणा

इत्तेमाद (12 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने अफ्रीकी देश यिथोपिया से दो हजार यहूदियों को फिलिस्तीन अधिकृत क्षेत्रों में बसाने की घोषणा की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि फिलासा नस्ल के यहूदी को फिलिस्तीन में आबाद किया जाएगा। इस योजना के लिए इजरायल ने 37 करोड़ शेकेल देने की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद से भी वार्ता की है। संयुक्त अरब अमीरात और बहर ीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद इजरायल सरकार ने फिलिस्तीन में अपने कब्जे को मजबूत बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। हाल ही में गाजा में इजरायल सरकार और फिलिस्तीनियों के बीच जोरदार झड़पें हुईं। मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होकर नमाज अदा करने की अनुमति सैनिकों ने नहीं दी। यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा के भीतर घुसने का प्रयास किया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने विश्वभर के मानवाधिकार संगठनों से अनुरोध किया है कि वे इजरायल द्वारा की जा रही आक्रामक कार्रवाईयों को रोकने के लिए आवाज बुलंद करें। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतयेह ने यह दावा किया है कि इजरायल सरकार पूर्वी रामल्ला में अरब स्कूलों को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है ताकि अरब बच्चों को वहां अरबी की शिक्षा न मिले। इस स्कूल में पहली से लेकर छठी कक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इजरायल सरकार ने अरबी माध्यम के कई स्कूलों को अवैध घोषित करके उन्हें ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए हैं। मस्जिद अल-अक्सा के खतीब अल-शेख एकरेमा सबरी ने यहूदियों को यह चेतावनी दी है कि वे मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करने की योजना से बाज आएं। वरना उन्हें तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के यहूदी अल-अक्सा की जगह पर हैकल सुलेमानी का निर्माण करना चाहते हैं। इस्लामिक जगत को इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन हफ्ते से इजरायली सेना अरबों को मस्जिद में दाखिल होने से रोक रही है और इस पवित्र मस्जिद को चारों तरफ से घेर रखा है।

ईरान और इराक की सीमा बंद

इंकलाब (6 अक्टूबर) के अनुसार कोरोना महामारी के कारण ईरान और इराक की सीमाएं अरबईन हसनी मार्च के लाखों यात्रियों के लिए बंद कर दी हैं।

इस्लामिक परम्परा के अनुसार हजरत इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन जो कि चेहल्लुम कहलाता है मुस्लिम देशों के लाखों यात्री पैदल यात्रा करते हुए कर्बला के मैदान में पहुंचते हैं और वहां पर कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। औसतन 40 लाख लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं और इसमें विश्वभर के शिया शामिल होते हैं। ईरान की सीमा सुरक्षा फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर अहमद गोदरजाई ने कहा है कि कोरोना की महामारी को देखते हुए इराक सरकार के अनुरोध पर सीमा बंद की गई है। इराक सरकार ने यह घोषणा की है कि इस बार अरबईन हसनी मार्च नहीं होगा। इसके बावजूद इराक में बसरा, नसीरिया और समावाह की ओर से श्रद्धालु सीमित संख्या में पैदल यात्रा कर रहे हैं। इराक की सेना ने इन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए हैं क्योंकि इराक सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि सुन्नी आतंकवादी इस मार्च पर घातक हमला कर सकते हैं।

सर सैयद के लेखों का प्रकाशन

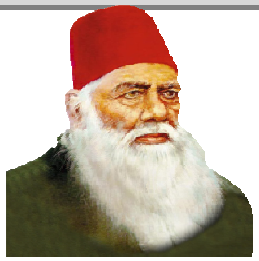

इंकलाब (8 अक्टूबर) के अनुसार आल्मी उर्दू ट्रस्ट ने यह निर्णय किया है कि अलीगढ़ विश्वविद्य ालय के संस्थापक सर सैयद अहमद की वर्षगांठ पर उनकी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा जो कि 25 खंडों में होगा। उनके लेखों के संग्रह की शुरुआत 1961 में शेख इस्माइल पानीपति ने की थी और मजलिस तरक्की अदब उर्दू लाहौर ने इसे 16 खंडों में प्रकाशित किया था। मगर उसके बाद कई अन्य पुस्तकें भी प्रकाश में आई हैं। इसलिए 2017 में सर सैयद अहमद की दूसरी शताब्दी के अवसर पर उनकी कुल पुस्तकों एवं लेखों को प्रकाशित करने का निर्णय किया गया था जो कि 17000 पृष्ठों पर आधारित है। उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन ए. रहमान ने कहा कि ये सभी 25 खंड अगले छह महीने में प्रकाशित होकर बाजार में आ जाएंगे।

सब्जियों के मूल्य में भारी वृद्धि

सियासत (9 अक्टूबर) के अनुसार गत दो सप्ताह में हैदराबाद में प्याज के मूल्यों में दोगुनी वृद्धि हो गई है। समाचारपत्र के अनुसार एक सप्ताह पूर्व हैदराबाद के बाजार में जो प्याज 40 रु. किलो बिक रहा था अब उसका मूल्य 80 रुपये तक पहुंच गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वर्षा के कारण प्याज की फसल खराब हो गई है। समाचारपत्र ने इस बात पर परेशानी प्रकट की है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के बावजूद सभी राजनीतिक दल खामोश हैं। समाचारपत्र का कहना है कि लॉकडाउन के कारण

खाद्य तेल, चावल, दाल, इमली और प्याज के मूल्यों में साठ से 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि सब्जी के भाव 40 से 100 प्रतिशत तक बढ़े हैं।

किफायती शादी करने का अभियान

मुंबई उर्दू न्यूज (10 अक्टूबर) के अनुसार मुसलमानों के विभिन्न वर्गों ने विवाह शादियों पर होने वाले अंधाधुंध खर्चों को रोकने के लिए राहत फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना की है, जिसकी ओर से महाराष्ट्र और तेलंगाना में यह अभियान चलाया जाएगा कि मुसलमान अपनी शादी-विवाह पर फिजूल धनराशि खर्च न क रें। निकाहों का आयोजन फेस्टिवल हॉलों में करने की बजाय मस्जिदों में किया जाए और समाज के भोज में केवल दो गोश्त की किस्में ही परोसी जाएं। सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद खान ने संवाददाताओं को बताया कि उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया था कि लॉकडाउन के कारण उनके 25 लाख रुपये खर्च होने से बच गए हैं। क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो उन्हें अपने बेटे की शादी की दावत पर अपना मकान और जमीन बेचनी पड़ती। मगर अब 50 मेहमानों में ही मामला निपट गया। इसके बाद उन्होंने रजा एकेडमी के महामंत्री सईद नूरी के प्रयासों से इस कार्य का आरम्भ किया है। फिलहाल उनका अभियान उनकी अपनी बिरादरी घाटक समाज तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि घाटक समाज को कुरैशी और कसाई समाज भी बोला जाता है। कपड़ा व्यापारियों ने भी किफायती शादी का अभियान महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में चलाने का निर्णय किया है।

हैदराबाद नगर की स्थापना का जश्न

सियासत (11 अक्टूबर) के अनुसार हैदराबाद नगर की स्थापना 429 वर्ष पूर्व की गई थी। इसकी आधारशीला 9 अक्टूबर 1551 को रखी गई थी। नया नगर बसाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि गोलकुंडा सिटी नामक राजधानी में आबादी बहुत बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त उस समय प्लेग की महामारी फैली थी जिसके कारण हजारों लोग मर गए थे। इसके बाद गोलकुंडा किले से दस किलोमीटर दूर इस नगर को बसाने का निर्णय

किया गया था। इस नगर की आधारशिला उस जगह रखी गई थी जहां पर इस समय चारमीनार स्थित है। तोजक कुतुबशाही नामक ऐतिहासिक पुस्तक के अनुसार इस्लामी विद्वानों ने यह निर्देश दिया था कि नए शहर की स्थापना के लिए सबसे पहले एक बड़ा ताजिया बनाया जाए जिसे चारमीनार का नाम दिया गया। इस शहर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। उस समय चारमीनार के निर्माण पर नौ लाख रुपये खर्च हुए थे। आज विश्व भर में हैदराबाद को एक विशेष सभ्यता के रूप में याद किया जाता है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग

इत्तेमाद (10 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश में हिन्दुओं, ईसाईयों और बौद्धों पर दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए हमलों के कारण असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। हाल ही में ढाका में हिन्दू अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया था जिसमें उन्हें बांग्लादेश छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी गई थी। अल्पसंख्यक परिषद के महामंत्री राणा दासगुप्ता ने एक वक्तव्य में कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है और ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है जिसके कारण भयभीत होकर अल्पसंख्यक बांग्लादेश से पलायन करने को विवश हो जाएं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सत्तारूढ़ दल अवामी लीग और जमात-ए-इस्लामी का पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों से अपील की है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जोरदार प्रयास किए जाएं और उन्हें इस बात की गारंटी दी जाए कि

उनके जान-व-माल का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि उसने अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को पारित करके लागू करने का जो आश्वासन दिया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। दासगुप्ता ने कहा कि आज बांग्लादेश में कोई भी मंदिर, गिरजाघर और बौद्ध मठ सुरक्षित नहीं है। सत्तारूढ़ दल के गुंडे खुलेआम उपासना स्थलों पर हमले कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है और उनकी महिलाओं का दिन-दहाड़े अपहरण किया जा रहा है।